

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2007—आषाढ़ 15, शक 1929

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2007

क्रमांक 1696/1075/2007/1/2.—श्री पी. रमेश कुमार, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 11-06-2007 से 15-06-2007 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 9, 10, 16, 17-06-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. रमेश कुमार आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पी. रमेश कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. रमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव।

**वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**

रायपुर, दिनांक 21 जून 2007

क्रमांक एफ-6-45/2007/वा.क. (पं.)/पांच.—राज्य शासन द्वारा श्री डी. सी. पांडेय, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 18-06-2007 से 23-06-2007 तक कुल 6 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री पांडेय, आगामी आदेश तक महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री पांडेय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पांडेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव।

**गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**

रायपुर, दिनांक 22 जून 2007

क्रमांक एफ-9-04/दो/गृह/07.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी, 2007 को प्रश्न-पत्र “विधि एवं प्रक्रिया” (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. नीलमणी टोप्पो	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
2.	सुश्री सोनल खण्डूजा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री सुनील चौधरी	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
4.	सुश्री सोनिया नायक	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
5.	सुश्री मीना मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
परीक्षा केन्द्र रायपुर			
6.	एस. आर. सोनकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. दिव्य, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जून 2007

क्र./2426/209-190/2006/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2007 के नियम 3 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, “प्रबंध संचालक” छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड को विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने, नवीकृत करने या देने से इंकार करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी/अधिकारी अधिसूचित करती है।

No. 2426/209-190/2006/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 3 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Special Licence for more than one market areas) Rules, 2007, the State Government hereby notifies the “Managing Director” of Chhattisgarh State Agriculture Marketing Board as Authority/Officer for the purpose of granting, renewing or refusing to grant the special licence.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2007

क्रमांक एफ-8-5/2007/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2), के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. चाम्पा के बायलर क्रमांक-एम. पी./4300 को दिनांक 25-06-2007 से 24-12-2007 एवं बायलर क्रमांक- एम.पी./4115 को दिनांक 12-07-2007 से 11-01-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :-

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
- (4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- (5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकर राव ब्राह्मणे, उप-सचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 25 अप्रैल 2007

क्रमांक/2444/भू-अर्जन/राप्रक्र/अ-82/06-07. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	फरसपाल	11.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ. ग.)	फरसपाल तालाब के निर्माण हेतु।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्टा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 जून 2007

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र.-22 अ 82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	तेलीबांधा प. ह. नं. 113	375	0.761	छ. ग. गृह निर्माण मं., संभाग क्रमांक-1.	दीनदयाल आवास योजनान्तर्गत निम्न आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु.
			376	0.257		
			377	0.571		
			378/1	0.465		
			378/2	0.405		
			379/1	0.203		
			379/2	0.198		
			379/3	0.194		
			379/5	0.194		
			379/4	0.198		
			380/1	0.140		
			387/1	0.411		
			380/2	0.139		
			387/2	0.140		
			381/1	0.129		
			381/2	0.134		
			381/3	0.110		
			388/1	0.223		
			388/2	0.405		
			388/3	0.229		
			389/1-2	0.190		
			390/1	0.534		
			390/2	0.025		
			390/3	0.074		
			390/4	0.083		
			390/5	0.054		
			390/6	0.116		
			390/7	0.053		
			406/1	0.068		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			406/2	0.170	
			406/4	0.105	
			406/3	0.101	
			406/5	0.101	
			406/6	0.037	
		योग	34	7.217	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि-उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-घरघोड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.593 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

10/1 ख, 12/1 ग, 12/1 घ, 12/1 ङ	0.108
12/3, 14, 15	0.575
17/1 झ	0.120
78, 79, 80/1, 81, 82, 100/2	1.517
96	0.410
97	0.081
145/1	0.607
145/3	0.405
145/4, 145/5	0.323

(1)	(2)
145/2, 283/1	0.243
281/3, 282, 283/2	0.243
284	0.243
285/1	0.101
285/2	0.101
285/3	0.101
285/4	0.101
297/2	0.014
286/1	0.244
287	0.024
276/3	0.251
277	0.008
286/2	0.283
274	0.096
273	0.413
265/2, 269/2, 272/4	0.060
265/1, 267/1, 268/1, 272/2,	0.728
265/2, 268/2, 272/3	
260	0.202
263	0.120
252	0.303
275	0.568
योग	8.593

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरघोड़ा बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

अनुसूची

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 जून 2007

क्रमांक 228/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
65/2, 71/2	0.045
योग	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोघरा मा.
नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी,
हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 जून 2007

क्रमांक 229/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-नंदौरखुर्द, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91/2	0.040
192/2	0.024
योग	2 0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नंदौरखुर्द
माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी,
हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 जून 2007

क्रमांक 230/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
456/10	0.020
476/2	0.060

(1)	(2)
475/7	0.020
योग 3	0.100

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमलीडीह ब्रां. सब मा. नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 जून 2007

क्रमांक/4507/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-किलारगोंदी, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.172 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.024
34	0.048
1/1	0.100
योग 3	0.172

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिए आवश्यकता है- मोंगरा बैराज परियोजना के बाँयी तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मोहला, जिला-राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 जून 2007

क्रमांक/4508/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-ब्राम्हणभेड़ी, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.410 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45	0.226
429/13	0.048
352	0.020
322/2	0.016
46	0.088
439/1	0.012

योग 6 0.410

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिए आवश्यकता है- मोंगरा बैराज परियोजना के बाँयी तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मोहला, जिला-राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.